<u>पंचायती राज मंत्रालय</u>

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की अक्तूबर, 2018 माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1) सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर, 2018 को आयोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की पहली बैठक में 18 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की वार्षिक कार्य योजना को चर्चा के उपरांत अनुमोदित किया गया। इसके अलावा योजना के केंद्रीय घटकों के तहत कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

2) आरजीएसए की योजना के तहत क्षमता निर्माण हस्तक्षेप करने के लिए उत्तर प्रदेश को 14.89 करोड़ रूपये तक की निधि जारी की गई ।

3) व्यापक प्रारंभिक गतिविधियों के बाद, शिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से राज्यों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए जन योजना अभियान को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर, 2018 को शुरू किया गया। यह अभियान 31 दिसंबर, 2018 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारी अपने विभाग की गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति देंगे।

4) अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए स्थापित अभियान के पोर्टल पर राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा डेटा नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए जहां भी आवश्यक हो, नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और हस्तक्षेप शुरू किए जा रहे हैं। जीपीडीपी अभियान में पिछड़ गए 14 राज्यों के साथ सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर, 2018 को आयोजित किया गया था । अपर सचिव, एमओपीआर द्वारा सभी राज्यों के साथ एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस 29 अक्टूबर, 2018 को आयोजित किया गया।
5) महीने के दौरान, अभियान का फोकस प्रत्येक ग्राम सभा के लिए सुविधा प्रदाताओं की नियुक्ति पर था। 82% से अधिक ग्राम सभा ने अब तक एक या एक से अधिक सुविधाप्रदाता नियुक्त किए हैं। अभियान का ध्यान अब मिशन अंत्योदय डेटा संग्रह और ग्रामसभा की बैठकों को निर्धारित करने पर होगा।

6) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में एमओपीआर के एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने 17-19 अक्टूबर, 2018 के दौरान स्थानीय शासन (थाल्ग) हेग अकादमी, नीदरलेंड में आयोजित "जेंडर उत्तरदायी शासन पर गोलमेज विचार-विमर्श सह प्रशिक्षण" में भाग लिया। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महिला (बहु-देशीय कार्यालय, भारत) द्वारा आयोजित किया गया था, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। संयुक्त राष्ट्र महिला ने "जेंडर उत्तरदायी शासन में वृद्धि के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण" कार्यक्रम के तहत जेंडर उत्तरदायी शासन पर अंतर्राष्ट्रीय जानकारी आदान-प्रदान करने हेतु अपनी पहल के एक हिस्से के रूप में इस गोलमेज विचार-विमर्श सह प्रशिक्षण का आयोजन किया था।

7) इस मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने इस महीने के दौरान केरल को 401.39 करोड़ रुपये, ओडिशा को 884.22 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को 33.535 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 188.095 करोड़ रुपये चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के मूल अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में जारी किए।

8) वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत मूल अनुदान के रूप में 29942.87 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में कुल 28600.45 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल आंवटन 34596.26 करोड़ की तुलना में 32157.00 करोड़ और वर्ष 2018-19 के आवंटन 40021.63 करोड़ रुपये की तुलना में 1,9168.907 करोड़ रुपये मूल अनुदान के रूप में निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2016-17 के लिए 3927.65 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 3499.45 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1106.90 करोड़ रुपये निष्पादन अनुदान के रूप में निर्मुक्त किए गए।

9) एफएफसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए गठित समन्वय समिति की 7 वीं बैठक 24 अक्टूबर, 2018 को निष्पादन अनुदान योजना की समीक्षा पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

10) पन्द्रहवें वित्त आयोग के लिए अनुपूरक ज्ञापन की सामग्री पर चर्चा करने के लिए 23 अक्टूबर, 2018 को पन्द्रहवें वित्त आयोग के लिए ज्ञापन तैयार करने हेतु एमओपीआर की सहायता के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।

11) ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए एफएफसी निधियों के मूल्यांकन पर अनुसंधान अध्ययन के आर्थिक विकास संस्थान के प्रस्ताव पर निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान द्वारा 23 अक्टूबर, 2018 को एक प्रस्तुति दी गई। यह अध्ययन 16 राज्यों के लिए प्रस्तावित है।

12) विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का सख्ती से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय वर्ष 2017-18 के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाते को बंद करने ग्राम पंचायतों / विक्रेता पंजीकरण के लिए राज्यों का अनुसरण करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए, 86% ग्राम पंचायतों ने अपनी खाता किताबें बंद कर दी हैं और 1,31,612 ग्राम पंचायतों ने पीएफएमएस पर पंजीकरण करा लिया है जबकि शेष ग्राम पंचायत इसकी प्रक्रिया में हैं। लगभग 65,571 ग्राम पंचायत पहले ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) खरीद चुके हैं।

13) इसके अलावा, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों में एलजीडी कोड को अपनाने पर बड़ा जोर दिया गया है। एलजीडी कोड के साथ ग्राम पंचायतों का मानचित्रण करने के लिए मंत्रालय पीएफएमएस टीम के साथ पूरी तरह से अनुसरण कर रहा है। आज तक, 90% ग्राम पंचायतों का एलजीडी कोड के साथ मानचित्रण कर लिया गया है।

****

Ministry panchayati Raj

Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of October, 2018

1) In the first meeting of the Central Empowered Committee (CEC) of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), held on 12th October, 2018 under the Chairmanship of Secretary, Panchayati Raj, the Annual Action Plans of 18 States namely Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Kerala, Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya and Nagaland were considered and approved. Besides, several proposals under central components of the Scheme were also considered and approved.

2) Funds to the tune of Rs. 14.89 crore were released to the State of Uttar Pradesh for undertaking Capacity Building interventions under the Scheme of RGSA.

3) After extensive preparatory activities for sensitizing the States and other Stakeholders through trainings and workshops, the People's Plan Campaign was formally launched on 2nd October, 2018. The Campaign will continue till 31st December, 2018 during which structured Gram Sabha meetings are to be held for preparing Gram Panchayat Development Plans (GPDP) for the next financial year 2019-20, where frontline officials of all line Departments relating to 29 subjects listed in the Eleventh Schedule of the Constitution will make a presentation regarding their Department's activities.

4) Data is being uploaded regularly by States and other Stakeholders on the portal of the Campaign established to monitor the progress of the Campaign. Regular follow-up

actions and interventions are being initiated wherever required for effective roll out of the Campaign. A Video Conference was held by Secretary, Panchayati Raj and Rural Development on 25th October, 2018, with 14 States which are lagging behind in GPDP Campaign. Another Video Conference with all States was also held by Additional Secretary, MoPR on 29th October, 2018.

5) During the month, the focus of the Campaign was on appointment of facilitators for each Gram Sabha. More than 82% of the Gram Sabhas have appointed one or more facilitators so far. The focus of the Campaign will now be on collection of Mission Antyodaya Data and scheduling Gram Sabha meetings.

6) An official delegation of MoPR led by Secretary, Ministry of Panchayati Raj and Rural Development visited The Hague, Netherlands during 17-19 October, 2018 for participating in the "Roundtable deliberation cum training on Gender Responsive Governance" organised at The Hague Academy of Local Governance (THALG). The programme was organised by UN Women (Multi-Country Office, India), which is the UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. UN Women organised the Roundtable deliberation cum training as a part of their initiative on International Knowledge Exchange on Gender Responsive Governance under the programme "A Multi-Sectoral Approach to Enhancing Gender Responsive Governance".

7) In accordance with the recommendations of this Ministry, the Ministry of Finance (MoF) has released during the month, 2nd instalment of Fourteenth Finance Commission (FFC) Basic Grant of Rs. 401.39 crore to Kerala, Rs. 884.22 crore to Odisha, Rs. 33.535 crore to Tripura and Rs. 188.095 crore to Uttarakhand for 2018-19.

8) The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 is Rs. 28600.45 crore against the allocation of Rs. 29942.87 crore, during 2017-18 is Rs. 32157.00 crore against the allocation of Rs. 34596.26 crore and it is Rs.19168.907 crore against the allocation of Rs.40021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3499.45 crore against the allocation of Rs. 3927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore, for the year 2017-18.

9) The 7th meeting of Co-ordination Committee, constituted for providing guidance and support to the State Governments and Local Bodies on implementation of the recommendations of FFC, was held on 24th October, 2018 to discuss about review of Performance Grant Scheme.

10) A Meeting of the Expert Committee to assist MoPR in preparation of Memorandum for XV Finance Commission was held on 23rd October, 2018, to discuss the contents of the supplementary memorandum to be submitted to XV Finance Commission.

11) A presentation was made on 23rd October, 2018, by Director, Institute of Economic Growth on their proposal for a research study on evaluation of FFC Funds to Gram Panchayats which is proposed to be conducted in 16 States.

12) As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously

pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 86% of the Gram Panchayats have closed their account books and 1, 31,612 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 65,571 GPs have already procured Digital Signature Certificates (DSCs).

13) Further, with a major emphasis on adopting LGD codes across all the Central Government Ministries and State Governments; the Ministry is thoroughly pursuing with the PFMS team to get the GPs mapped with LGD codes. As on date, 90% of Gram Panchayats are mapped with LGD codes.

****